



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, २६ जुलाई, २००३/४ भाद्रपण, १९२५

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, २६ जुलाई, २००३

संख्या एल० एल० आर० डी० (६)-२४/२००३-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान
के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक २६-७-२००३ को

१६९८-राजपत्र/२००३-२६-७-२००३-१,४५५.

(९९९)

मूल्य : एक रुपया ।

उपायुक्त,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ।

प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अध्यादेश 2003 (2003 का अध्यादेश संख्यांक 6) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2003

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का 13) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा मंत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है ;

अतः हिमाचल के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 है । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

(2) यह 30 मई, 1994 को प्रवृत्त होगा और प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में, “तथा उसके ऐसे अनुलग्नकों या फर्नीचर की दशा में जो उसके साथ उपयोग या उपभोग के लिए” शब्दों के स्थान पर “की दशा में सकल वार्षिक किराया, जिस पर कि ऐसा गृह या निर्माण, इसके अनुलग्नकों और किसी प्रकार के फर्नीचर सहित जो उसके साथ उपयोग या उपभोग के लिए किराए पर दिया जा सकेगा,” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे । धारा 2 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 के प्रकाशन पर या इससे पूर्व किसी भी समय मूल अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन अवधारित किया गया किसी गृह या निर्माण (बिल्डिंग) का वार्षिक मूल्य, किया गया कोई निर्धारण या की गई कर की वसूली या की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन विधिमाम्यतः और विधि पूर्वक अवधारित, निर्धारित, वसूल की गई, की गई और सदैव की गई समझी जाएगी । विधिमाम्य-करण ।

विष्णु सदाशिव कोकजे,
राज्यपाल हिमाचल प्रदेश ।

सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

शिमला
तारीख 26 जुलाई, 2003.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 6 of 2003

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL
(THIRD AMENDMENT) ORDINANCE, 2003

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India.

AN

ORDINANCE

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (13 of 1994)

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title
and com-
mence-
ment,

1. (1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Municipal (Third Amendment) Ordinance, 2003.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force on the 30th Day of May, 1994.

Amend-
ment of
section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), in clause (b), for the words "together with its appurtenances or any furniture that may be let for use and", the words "the gross annual rent at which such house or building, together with its appurtenances and any furniture that may be let for use or" shall be substituted.

Validation.

3. Notwithstanding anything to the contrary contained in the principal Act, any annual value of house or building determined, any assessment or recovery of tax made or any action taken or anything done under the provisions of the principal Act, at any time on or before the publication of the Himachal Pradesh Municipal (Third Amendment) Ordinance, 2003 shall and shall always be deemed to have been validly and lawfully determined, assessed, recovered, taken or done under the provisions of the principal Act as amended by this Ordinance.